मंदिर पर कब्जे की लड़ाई, प्रशासक ने सत्ता हथियाई

फरीदाबाद (म.मो.) एनआईटी एक नंबर स्थित श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर पर आजकल महाभारत चल रही है। यहां के एक पक्ष के प्रधान राजेश भाटिया को खतरा है कि कहीं प्रशासन वहां प्रशाक नियुक्त न कर दे। दूसरे पक्ष के नेता जोगेंद्र चावला का दावा है कि जब कोर्ट ने राजेश भाटिया मंदिर से रेस्ट्रेन कर रखा है, तो वे क्यों मंदिर के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी झगड़े का आधार बना कर ज़िला प्रशासन ने सिटी मैजिस्ट्रेट गौरव अंतिल को 14 अक्तूबर को मंदिर का प्रशासक नियुक्त कर दिया।ध्यान रहे कि श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर मामले में राजेश भाटिया द्वारा स्टेट रजिस्ट्रार के समक्ष दो अपील डाली गई थीं, जिसकी तारीख 6 अक्टूबर थी। सूत्रों के अनुसार तीन महीने इंतजार करने के बाद भी राजेश भाटिया की दोनों अपील खारिज कर दी गई हैं। बता दें कि यह दोनों अपीलें राजेश भाटिया ने 28 जुलाई को डाली थी। राजेश भाटिया ने अपनी एक अपील में जहां अपने आप को सिद्धपीठ का प्रधान रखने की गुजारिश की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्टेट रजिस्ट्रार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत द्वारा स्पष्ट है कि राजेश भाटिया को कोर्ट ने रेस्ट्रेन कर रखा है, इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट रजिस्ट्रार ने यह पहली अपील खारिज कर दी।

वहीं दूसरी अपील राजेश भाटिया ने मंदिर में प्रकाशक न नियुक्त किया जाएए इसके लिए दायर की थी लेकिन स्टेट रजिस्ट्रार ने उसे भी खारिज कर दिया। स्टेट रजिस्ट्रार ने दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा कि अभी तक मंदिर में प्रकाशक नियुक्त करने के लिए कोई आर्डर पास नहीं किया गया है और जब तक आर्डर ही पास नहीं किया गया तो फिर अपील दायर करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। दूसरी तरफ जोगेन्द्र चावला ने बताया कि राजेश भाटिया को कोर्ट ने रेस्ट्रेन कर रखा है, उसके बावजूद वह लोगों, प्रशासन व नेताओं को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं वह कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय शहर के त्यौहार का माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। चूंकि राजेश भाटिया कानूनी तौर पर मंदिर का सदस्य भी नहीं हैं, परन्तु वह अपने परिवार के राजनीतिक दम का फायदा उठा रहा है। जोगेन्द्र चावला ने लोगों से आग्रह किया है कि जो भी संस्था अपना रावण दशहरा मैदान में लाना चाहती है वह निशुल्क अपनी जगह लेने के लिए सूचित कर सकती है। दशहरा इस बार भी हर वर्ष की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा।

असल माजरा

मंदिरों की अकूत संपदा का लाभ और उपयोग वहां के पुजारी और कर्ता-धर्ता करते नजर आते हैं। जबकि उसका उपयोग मंदिर रखरखाव उसके विस्तार, भोजनालय, विश्रामालय, पुस्तकालय, औषधालय, चिकित्सालय, शिक्षालय, क्रीडालय आदि सामाजिक कल्याण के कार्यों पर होना चाहिए। मंदिर आस्था के केंद्र होते हैं। लेकिन मंदिर में बढ़ते चढ़ावे और चौधराहट ने अब मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। मंदिरों की चौधराहट में तलवारें चलती हैं और गोलीबारी तक हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों। क्या मंदिर के संचालकों में सेवा की इतनी उत्कट इच्छा होती है कि वे अपने सिवा और किसी को सेवा करने का मौका नहीं देना चाहते और गोलीबारी तक पर उतारू हो जाते हैं। अगर विशुद्ध सेवा की भावना भी किसी संचालक के मन में हो, तो सेवा का अधिकारी अन्य व्यक्ति भी उतना ही होता है। मंदिर की सेवा में सबका साझा हिस्सा है। किसी को कैसे रोका जा सकता है। स्वाभाविक समझ कहती है कि जब सेवा की आड़ में बदनीयती प्रबल हो जाती है और मंदिर की संपदा पर लार टपकने लगती है, तब भी टकराव और पटेबाजी होती है।

राजनीति और धर्म

पूर्व विधायक कुंदनलाल भाटिया के पांच पुत्र जगदीश, चंदर, गोबिंद, काले और राजेश भाटिया है। कुंदन की मौत के बाद चंदर विधायक बने। जगदीश भाटिया एनआईटी एक के माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रधान बन गए। राजेश भाटिया हनुमान मंदिर के प्रधान बन गए। जगदीश भाटिया व्यापार मंडल के भी प्रधान हैं। प्रधानी की गहरी होती लालसा उन्हें वैष्णो देवी मंदिर तक ले आई। वैष्णो मंदिर के आधुनिक स्वरूप भव्यता और मान्यता प्रदान करवाने में डिलाइट होटल के मालिक रामशरण भाटिया का योगदान कोई भी खारिज नहीं कर सकता। यहां ऐसा विवाद हुआ कि शांतिप्रिय रामशरण भाटिया ने मैदान छोड़ दिया और जगदीश भाटिया काबिज हो गए। राजेश भाटिया ने जिस तरह हनुमान मंदिर में एंट्री मारी और प्रधानी हथियाई, उसके तौर.तरीकों पर बिरादरी को ऐतराज है और इस असरदार परिवार के रसूख के बावजूद उनके खिलाफ जोगेंद्र चावला झंडा उठाए हुए हैं।

धौंस तो देखिए

प्रशासन कहीं हनुमान मंदिर पर प्रशासन न बिठा दे। इस बात से भयभीत भाटिया परिवार ने हाल ही में मंदिर के सामने अपना शक्तिप्रदर्शन करते हुए सभा की। इसमें पूर्व विधायक चंदर भाटिया ने जो.जो बोला उसके निहितार्थ ही इस परिवार की पोल खोलते हैं। चंदर भाटिया ने सबसे पहले तो हनुमान मंदिर में चल रहे खेल का ठीकरा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सीमा त्रिखा पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि जीजा.साली का खेल मंदिर में नहीं चलने देंगे। हालांकि सूत्रों का भी कहना है कि विरोधी गुट को सीमा त्रिखा हवा दे रही हैं। चंदर भाटिया ने कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देते हुए कहा कि गुर्जर की तरह वे भी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। वे हार गए थे और गुर्जर नरेंद्र मोदी की लहर में जीत गए थे। गुर्जर अपने साथ नरेंद्र मोदी का नाम हटा कर उनके मुकाबले चुनाव लड़ लें तो उन्हें हैसियत का पता चल जाएगा। चंदर भाटिया ने प्रशासन, पुलिस को अपना इतिहास बताते हुए कहा कि उन्होंने बंसीलाल और चौटाला सरकारों से लोहा लिया है। एनआईटी नंबर एक में जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा था तो उन्होंने अधिकारियों को भगा दिया था। एनआईटी दो में जब आरा मशीनें हटाने की बात आई तो भी नगर निगम अधिकारियों को भगा दिया था। जब इंदिरा कालोनी तोड़ने का मामला था, तो भी वे पुलिस से भिड़ गए थे। चंदर भाटिया अपने इस तरह की बयानबाजी करके कदाचित यह जतलाना चाहते हैं कि प्रशासन अब मंदिर पर प्रशासक बिठाता है तो वे यहां से भी अधिकारियों को खदेड़ देंगे। चंदर भाटिया इस खेल में इतने आक्रामक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कोई निजी संपत्ति छिनती हुई दिखाई दे रही हो।

टकराव की आशंका

भाटिया परिवार अपनी आक्रामकता के लिए कुख्यात है। दशहरा पर राजेश भाटिया रावण अपने नेतृत्व में जलवाने की जिद किए हुए हैं। जबकि जोगेंद्र चावला ऐसा होने नहीं देना चाहते। ऐसे में टकराव हो सकता है। प्रशासन को भी इसका पूर्वानुमान है, क्योंकि मंदिर के सामने जब चंदर भाटिया ने 200 लोग़ों की सभा की थी, तो 50 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात थे।

लोगों को इंतजार है

एनआईटी के लोग अभी इस बात को नहीं भूले हैं कि किस तरह सूदखोरी के दौर में दर्जनों युवाओं ने खुदकशियां की थीं। किस तरह क्रिकेट का सट्टा खिलाकर युवाओं के जीवन को बरबाद किया गया। किस तरह मंदिर कब्जाए गए। लोग दम साधकर इस इंतजार में बैठे हैं कि कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कहीं एक राजनेता के हाथ से मंदिर निकलकर किसी दूसरे राजनेता के हाथ में तो नहीं पहुंच जाएगा। क्या प्रशासन इन नेताओं को लताड़कर मंदिर में राजनीति विहीन नेतृत्व स्थापित करने का साहस दिखा पाएगा।

सरकारी लूट के विरुद्ध ट्रांसपोर्ट हड़ताल

फ़रीदाबाद (म.मो.) किसी भी शहर से किसी भी सड़क पर निकल लो हर 20-30 किलोमीटर पर सरकारी लूट के नाके लगे हैं, जिन्हें नाम दिया है टोल टैक्स। वैसे तो यह लूट 1990 के दशक में शुरू हो गयी थी लेकिन इसको पूरी गति मिली वाजपेयी सरकार में जब एनएचएआई (भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) का गठन किया गया। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के नाम पर बनाया गया यह प्राधिकरण देखने-सुनने में तो बहुत अच्छा लगा था; एक उम्मीद जगी थी कि अब बेहतर सड़कें उपलब्ध होंगी और सड़क यातायात सुगम होगा।

यातायात सुगम करने के नाम पर सरकार ने एनएचएआई के माध्यम से एक के बाद एक सड़क को बेचना शुरू कर दिया। जब तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग बेच खाये तो राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम देकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। पानीपत से गोहाना रोहतक-रेवाड़ी तथा अम्बाला से कैथल-बरवाला-हिसार होते हुए राजस्थान को जाने वाली सड़कें इसी श्रेणी में आती हैं। पूरी नाटकबाज़ी के साथ इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके उन पर सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया जाता है। लेकिन एलान करते वक्त कोई ड्रामेबाज़ नेता यह नहीं बताता कि यह सारा खर्चा टोल टैक्स के माध्यम द्वारा जनता से ही वसूला जायेगा, यहां तक कि सारी उम्र वसूला जाता रहेगा।

यह ठीक है कि सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिये काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। सैंकड़ों वर्षों से, जब से ये सड़कें बनी हैं, जनता इसके लिये विभिन्न टैक्सों के रूप में धन देती आई है। जब भी कोई वाहन सड़क पर उतरता है वह पंजीकरण शुल्क देकर उतरता है। पहले यह प्रत्येक वर्ष लिया जाता था जो अब 15 वर्ष अग्रिम एक साथ ले लिया जाता है। आरम्भिक योजनानुसार यह वाहन की आयुपर्यन्त होता था परन्तु अब 15 वर्ष बाद पुन: वसूलने लगे हैं। शोरूम से निकलने वाले वाहन से एक माह का अस्थाई शुल्क अलग से लिया जाने लगा है। इतना ही नहीं पहले यह शुल्क दुपहिया, कार व भारी व्यापारिक वाहनों की 4-5 श्रेणियों में बंटा होता था जो सैंकड़ों या हज़ारों में होता था। अब प्रत्येक वाहन अपने आप में एक श्रेणी है। उसकी कीमत के प्रतिशत के अनुसार पंजीकरण शुल्क वसूला जाता है। यह शुल्क अब हज़ारों लाखों में होने लगा है।

उक्त शुल्क के अलावा यात्री कर, सामान कर, परमिट फ़ीस आदि-आदि से भी जब लुटेरी सरकारों का पेट नहीं भरा तो डीजल-पैट्रोल पर सड़क सरचार्य के नाम पर अलग से वसूली होने लगी। इसके बाद सड़कों को बेचना शुरू कर दिया गया। रिलायंस व सोमा जैसी अनेकों कम्पनियां इस लूट का माध्यम बनी। हड़ताल पर जाने से पूर्व ट्रांसपोर्टस ने सरकार को ऑफ़र दी थी कि टोल टैक्स के माध्यम से सरकार को जितना पैसा मिलता है उतना पैसा वह उनसे एकमुश्त ले-ले ताकि रोज-रोज टोल नाकों पर खड़े होकर उन्हें समय और डीज़ल बर्बाद न करना पड़े। परन्तु सरकार को यह सुझाव रास नहीं आया। दरअसल इसके पीछे असली राज की बात यह है कि टोल वसूली की कुल रकम में से सरकारी खजाने में तो महज एक चौथाई भाग ही जाता है शेष तीन चौथाई ठेकेदार कम्पनियों, नेताओं व अफ़सरों में बंट जाता है। इसलिये कोई भी सरकार लूट के इस कारोबार को कभी भी बंद नहीं करना चाहेगी।

फ़रीदाबाद से आगरा के बीच के राजमार्ग का ठेका रिलायंस कम्पनी के पास है। गत करीब 5 वर्षों से कम्पनी टोल के नाम पर लूट में जुटी है जबकि सड़क पर काम करना उसने अभी 7-8 माह से ही शुरू किया है। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कम्पनी कुल वसूली का मात्र एक चौथाई भाग ही सड़क पर लगा रही है शेष अपनी विभिन्न कम्पनियों में निवेश कर रही है। इसी के चलते काम की रफ़्तार बेहद धीमी और असुरक्षित तरीके से चल रही है।

समाचार लिखते-लिखते बेशक बिना किसी ठोस नतीजे के ट्रकों की हड़ताल खुल गयी; लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, इस 5 दिन की हड़ताल ने व्यापक प्रभाव डाला है। ढुलाई न हो पाने के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बढ गये। कारखानों का उत्पादन ठप हो गया। इस से जहां एक ओर सरकार को अरबों रुपये के राजस्व की हानि हुई वहीं पूरे देश की जनता को जो हानि हुई वह तो इससे भी कहीं अधिक रही।

लेकिन सरकार को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देश की जनता मरती है तो मरे, घाटा होता है तो होता रहे, नेताओं व कम्पनियों की लूट में कोई कमी नहीं आनी चाहिये।

एनआईए की पोल खोली उसी के वकील ने

दिल्ली (म.मो.) नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की पोल खुद उसी के वकील ने खोल कर उसे बीच चौराहे के नंगा कर दिया। एनआईए की सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दिये अपने शपथपत्र में खुलासा किया है कि एनआईए के मुंबई में तैनात पुलिस अधीक्षक सुहास वर्के ने पहले उन्हें फ़ोन किया लेकिन फ़ोन पर पूरी बात न करके व्यक्तिगत रूप से मिल कर अपने उच्चाधिकारियों का संदेश दिया। इसमें कहा गया था कि वे कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान मालेगांव धमाकों के आरोपियों के साथ नरमी बर्तें। दूसरे शब्दों में इन हिन्दुत्ववादियों को इस केस में बरी कराना है। 'मज़दूर मोर्चा' के सुधी पाठकों ने 16-31 जुलाई अंक में 'अमितशाह की जेब में सीबीआई-शरद कुमार ने एनआईए बिकवाई' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट अवश्य पढी होगी। इसमें सीबीआई के साथ-साथ एनआईए के भीतर चलने वाले घाल-मेल का खुलासा किया गया था।

इस में स्पष्ट कर दिया गया था कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी सरकार के द्वारा अपने उन स्वंयसेवक संघ, मोदी सरकार के द्वारा अपने उन स्वंयसेवकों को बचाने का प्रयास कर रहा है जो मालेगांव धमाकों व समझौता एक्सप्रेस कांड में लिप्त थे।

रोहिणी सालियान का शपथपत्र जहां एक ओर 'मज़दूर मोर्चा' में प्रकाशित रिपोर्ट पर मुहर लगाता है वहीं इस बात की भी पुष्टि करता है कि आरएसएस किस प्रकार से भगवा आतंकवाद को बढावा दे रहा है।

पुलिस की लूट कमाई का एक और धंधा

पुलिस की लूट-कमाई में सट्टेबाज़ी शराब तस्करी गेस्ट हाउसों में चलती वेश्यावृत्ति, जुएबाज़ी, जैसे गोरखधंधे करने वालों की अहम भूमिका रहती है। इन धंधों से ज़्यादा शोर-शराबा नहीं होता लेकिन इनसे पनपने वाले जुर्म काफ़ी बड़े होते हैं। इसी लूट कमाई के चलते पुलिस के संरक्षण में थाना एनआईटी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित गांधी कॉलोनी में आधा दर्जन से अधिक सट्टेबाज़ बीच सड़क में कुर्सी मेज डाल कर सट्टे की पर्चीयां बेच रहे हैं। साथ ही इसी कॉलोनी में एक दर्जन से अधिक घरों में शराब तस्कर धड़ल्ले से अवैध शराब बेचने का धंधा भी कर रहे हैं।

इसी थाना क्षेत्र के एनएच 5 नम्बर का शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें एक दो शराब तस्कर अवैध शराब का धंधा न कर रहे हो। एन.एच 5 सी/ब्लॉक हरबंस, पाला सरदार जमकर अवैध शराब का धंधा बीच सड़क में दिन-दहाड़े कर, पुलिस कमिशनर के आदेशों की हवा निकाल रहे है। ये लोग 5/ सी ब्लॉक में सट्टे की पर्चियां बेच स्कूली बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं। सूत्रों अनुसार पाला सरदार को थाना एनआईटी पुलिस ने बी.सी का खिताब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसके भाई हरबंस (राजू) पर भी मुकदमे दर्ज है। जब कोई स्थानीय निवासी पुलिस थाना में शिकायत करता है तो वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी इनको पकड़ने की बजाय यह कहकर पिंड छुड़वा लेता है कि कितनी बार जाएं कितने मुकदमे दर्ज करें। सुबह पकड़ो तो रात तक फ़िर काम शुरू हो जाता है। रात को पकड़ो तो अगले दिन कोर्ट से जमानत लेकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं।

ठीक इसी तरह 5 एल/ब्लॉक में, जहां डीसीपी व एसीपी के दफ़्तर हैं, वेस्यावृत्ति का धंधा जमकर चल रहा है। इनके दफ़्तर के ठीक सामने बने तिकोना पार्क में भी रोज़ाना लाखों रुपये का जुआ व सट्टा खेला जाता है। अक्सर पुलिस वालों व सी आई ए स्टाफ़ के जवान वहां से अपना-अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। जिसके चलते इन गोरखधंधा करनेवालों के हौसले बुलंद हैं।

एन.एच.5 के मित्तल काम्पलैक्स में भी आधा दर्जन ब्याज खोर अपनी-अपनी दुकाने खोले बैठे हैं जिनके पास फ़ाइनेंस कम्पनी चलाने का कोई लाइसैंस नहीं है जो कि मनमाने तरीके से लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ब्याज पर रुपये देने का धंधा कर रहे हैं। पिछले दिनों एन.एच 5 के एम ब्लॉक में एक प्रोपर्टी विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ़ थाना एनआईटी में शिकायत की थी। जिसको लेकर थाना एनआईटी में तैनात एस.आई दिनेश ने एक पक्ष से 50000 रुपये की मांग कर दी थी लेकिन देर रात दोनों पक्षों का समझौता हो गया। लेकिन पुलिस बगैर अपनी फ़ीस, लिये समझौता मानने को तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बिना एफ़आईआर के एस.आई दिनेश ने उसे हवालात में बंद रखा जब उसके परिवार वालों ने व ससुराल पक्ष ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे छोड़ा। जब शिकायतकर्ता के परिवारवालों ने थाने में शोर-शराबा किया तो थाना एनआईटी में तैनात रह चुका एएसआई कैलाश को थाने में बुलाया गया। कैलाश ने सबके लिये चाय मंगाई व मामले को शान्त किया। जबकि दूसरे पक्ष से भी एसआई दिनेश के सामने थाने में तैनात संदीप ने 20000 रुपये की मांग की जिसकी जानकारी थाना प्रभारी नरेश को भी दी गई। लेकिन बावजूद इसके थाना प्रभारी ने एसआई दिनेश व संदीप को पूछा तक नहीं बल्कि दोनों पक्षों को धमका कर बाहर निकाल दिया जब इलाके का एसएचओ ही बिकाऊ हो तो ऐसी स्थिति तो होगी ही।